

अ**साधारम्** EXTRADEDENARA

und H--Tog 3-34-Tos (ii) FART 18--Section 3--Sub-Section (ii)

histor a madan Marianta ay All'indikity

er. 428

नई दिल्ली, मुक्तभार, जुलाई 27, 1990/श्रावण 5, 1912

N = 4281

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 1990/SRAVANA 5, 1912

इस भाग भें भिन्न पृथ्ठ संख्या की जाती हो जिस से कि यह अलग संप्रापन के रूप रा रामा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मन्नालय

(क्यंप श्रोर सहकारिया विनास)

ादेश

न्छ । तमे 27 ज्यारी १८३०

हा। आत. 594(आ):—- महुदाउध सह तार्थ स्तिताङ्क दी शिक्षिन्यम्, 1984 (1984) का 51) की (जिति दामें इसके प्रकास् प्रक्षिणयत प्रमुक्त का 3), धामा ४८ की उपवास (।) मीं यह उपवास १ कि आपे किसी अहुदाज सहकारा ता शहरते के पिद्रमत बोर्ड का अधिकाण किया जाता है हा बेन्तीय सी द्वार (है ते अध्यात समायकों की सीमाइटी के कार्यकलायों का एक वर्ष से अनिधिक भी एसी अविध के लिए जो समाज केन्द्रीय राजस्ट्रा के विवेक पर, समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु जिसकी कुल श्रयिश दो वर्ष से श्रिकिक नहीं होगी, प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा;

श्रीर नेशनल कोग्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेंडरेशन श्राफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की बाबत प्रशासक की नियुक्ति के लिए दो वर्ष की उक्त श्रवधि 14-10-89 की समाप्त हो चुकी थी।

श्रीर भारत सरकार के कमश:का . थ्रा. सं. 796(ग्र) तारीख 9 धक्तूबर, 1989 श्रीर का. थ्रा. 519 (ग्र) तारीख 28 जून 1990 द्वारा नेशनल कोग्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेंड की बाबत श्रिधनियम की धारा 48की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट प्रदान करके प्रशासक की नियुक्ति की श्रवधि को 30-6-90 श्रोर् 30-7-90 तक बढ़ा दिया गया था;

ग्रीर नागरिक पूर्ति विभाग ने जो नेशनल कोप्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग हैं, 31 ग्रगस्त, 1990 तक की ग्रीर श्रवधि के लिए प्रशासक को बनाए रखने की मिकारिण की है, जिसमें कि नेशनल कोग्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड निर्वेणक बोर्ड का पुनर्गठन कर सके।

भीर कृषि भीर सहकारिता विभाग ने यह आवश्यक समझा है कि नेशनल कोआ-परेटिब कन्ज्यमुर्स फेडरेशन आफ इण्डिया लिभिटेड के निवेशक बोर्ड के निविश्त कराने के प्रयोजन के लिए भ्रधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों से छूट की अविधि को 30 जुलाई, 1990 के पण्चात् 31 श्रगस्त, 1990 तक श्रीर बढ़ाया जाए।

म्रत: ग्रंब केन्द्रीय सरकार, भ्रधिनियम की धारा 899 की उपवारा (2) द्वारा प्रयंत मिन्तियों का प्रयोग करने हुए नेमनन कांग्रापरेटिव कन्ड्यूमर्ग फैंडरेगन म्राक इण्डिया लिमि नई दिल्ली को प्रधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों मे उस सीमा तकछूट देती है जिस तक प्रशासक नेमनल कोम्रापरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेगन म्राक इण्डिया लिमिटेंड, के कार्यकलापों का 31 अनसा, 1990 तक की ग्रीर अविधि के लिए प्रबंध करेगा।

> [सं. एल ~11011 / 11 / 89 एल ए**ड** एम] प्रालोक भटनागर, श्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agri. & Cooperation) ORDER

New Delhi, the 27th July, 1990

S.O. 594(E).—Whereas sub-section (1) of section 48 of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the Multi-Sta Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred to as the section of the

'Act') provides that where the Board of Directors of a multi-state cooperative society is superseded, the Central Registrar may appoint one or more administrators to manage the affairs of the society for such period not exceeding one year which period may, at the discretion of the Central Registrar, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period does not exceed two vears:

And whereas, the said period of two years for the appointment of administrator in respect of National Cooperative Consumers Federation of India Ltd., New Delhi expired on 14-10-89;

And whereas, the period of appointment of the administrator was extended -for a further period upto 30-6-90 and 30-7-90 by granting an exemption from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act in respect of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited as per S.O. No. 796(E) dated 9th October, 1989 of the Government of India and S.O. No. 519(E) dated 28th June, 1990 respectively;

And whereas, the Department of Civil Supplies, the administrative department for the National Cooperative Consumers Federation of India Limited has recommended the continuance of the administrator for a further period upto 31st August, 1990 to enable the National Cooperative Consumers Federation of India Limited to reconstitute the Board of Directors of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited.

And whereas, the Department of Agriculture and Cooperation considered it necessary further to extend the period of exemption beyond 30th July, 1990 and upto 31st August, 1990 from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act for the purpose of holding election to the Board of Directors of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Act, the Central Government hereby exempts the National Cooperative Consumers Federation of India Limited, New Delhi from provisions of sub-section (1) of ection 48 of the Act to the extent that the administrator will manage the affairs of the National Cooperative Consumers Federation of India Limited for a further period upto 31st August, 1990.

> [No. L-11011|11|89-L&M] ALOK BHATNAGAR, Under Secy.

